## अगले हफ्ते जारी होगी उत्तर, पूर्वोत्तर रेलवे की पिंक बुक ट्रैक मेंटेनेंस, यार्ड रीमॉडलिंग, सेफ्टी से जुड़े काम होंगे

# लखनऊ और कानपुर के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन जल्द

**बजट**

**240** करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद | **2.62** लाख करोड़ रुपये रेलवे को आवंटित

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। केंद्रीय बजट में भारतीय रेल को रफ्तार देने और यात्रियों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है। लखनऊ से कानपुर के लिए सेमी हाईस्पीड वंदे मेट्रो जल्द ही पटरी पर उतर सकती है। इसके लिए बजट में 240 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद रेलवे के अफसरों ने जताई है। इसी तरह गोमतीनगर से भोपाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, जम्मूतवी-कटरा और पुरी के लिए नई ट्रेन की सौगात भी यात्रियों को मिलने की उम्मीद इस बजट से जग गई है।

आम बजट में रेलवे को कुल 2.62 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। इसमें सेफ्टी व मेंटीनेंस के मद में 1.08 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस बजट में उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडलों को सेफ्टी, यात्री सुविधा और सुरक्षा के अलावा स्टेशनों के विकास के लिए बजट में हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद अफसरों को है। लखनऊ मंडल में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, इसकी सटीक जानकारी अगले हफ्ते पिंक बुक जारी होने पर मिलेगी।

### फोरलेन आउटर बनेगा, घटेगी लेटलतीफी

चारबाग से दिलकुशा व आलमनगर की ओर फोरलेन आउटर बनाया जाना है। दिलकुशा आउटर के लिए काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इस मद में अच्छी-खासी धनराशि मिलेगी। फोरलेन आउटर बन जाने से ट्रेनों की लेटलतीफी घटेगी तथा ट्रेनों को आउटर पर रोकने से यात्रियों को होने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी।

## सुनियोजित विकास से सड़कों पर घटेगा यातायात

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। आने वाले वर्षों में शहर की सड़कों से ट्रैफिक का भार घटाया जाए, इसके लिए केन्द्र सरकार ने प्रयास शुरू किया है। टीओडी जोन के तर्ज पर अब लखनऊ का विकास होगा। शहर के प्रमुख इलाकों से आने वालों को जहां मेट्रो सुविधाएं मिलेंगी वहीं नए इलाकों का ऐसे सुनियोजित विकास कराया जाएगा ताकि लोगों को शहर के अंदर कम से कम आना पड़े। जिन सेवाओं और सुविधाओं के लिए वे शहर में आते हैं वह उनके इलाके में ही मिल जाएं। केन्द्र सरकार ने बजट में आवागमन उन्मुखी विकास योजना पर काम शुरू करने का प्रावधान किया है। फिलहाल सबसे पहले देश के उन 14 शहरों को चुना गया है, जिनकी आबादी 30 लाख से अधिक है। ऐसे में लखनऊ को भी इसका फायदा मिलेगा।

30 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है।

इनमें सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी वजह से केन्द्र सरकार ने 14 शहरों को आवागमन उन्मुखी विकास योजना से जोड़ने का फैसला किया है। एलडीए से रिटायर टाउन प्लानर ने बताया कि यह कुछ टीओडी जोन की तरह होगा। सरकार की मंशा है कि ज्यादा आबादी वाले शहरों की सड़कों से वाहन घटाए जाएं। यह तभी संभव है, जब लोग शहर में कम रहें या आएं। जिले ही नहीं, आस पास के जिलों के लोग भी रोजगार के अलावा अस्पतालों में इलाज, सरकारी विभागों में कामों और न्यायालयों के लिए आते हैं। शहर और जिले के लोगों को भी आना जाना पड़ता है। सरकार की मंशा है कि लोगों को अपनी गाड़ियों से न आना पड़े। आस पास ही सुविधाएं विकसित कर दी जाएं ताकि घर से निकलते ही जरूरतें और काम पूरे हो जाएं। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मजबूत की जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण से हाल में रिटायर मुख्य अभियन्ता एके सिंह के मुताबिक सरकार की मंशा आस पास छोटे छोटे सुनियोजित शहर विकसित करने की है। जहां सरकारी दफ्तर भी हों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा भी रहे। इससे लोग शहरों की तरफ नहीं आएंगे। आस पास ही रोजगार के साधन हों। कोई इण्डस्ट्री या उद्योग हों तो पूरी सुविधा भी परिसर में मिल जाए। इससे लोगों को शहर आने से मुक्ति मिलेगी। सिंह के मुताबिक कुल मिलाकर सरकार टीओडी जोन की तरफ जा रही है।